यूपी में हो रहा सौर ऊर्जा का विकास हर डिस्कॉम का लक्ष्य निर्धारित

पीएम सूर्य घर योजना में यूपी के 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में सौर व जैव ऊर्जा का लगातार विकास किया जा रहा है। इसके लिए डिस्कॉमवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत यूपी के 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। इसमें लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना के तहत अभी तक 18,18,290 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1,88,209 प्रार्थनापत्र जमा हो चुके हैं। इनमें से 26,996 सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार 8,033 लोगों को सब्सिडी दे जा चुकी हैं।

वहीं, उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के बाद बची राशि पर 7% के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा। एक किलोवाट के सोलर रूफटॉप पर केंद्र 30 हजार और राज्य 15 हजार रुपये दो किलोवाट पर केंद्र 60 हजार व राज्य 30 हजार यानी कुल 90 हजार रुपये, तीन किलोवाट पर केंद्र 78 हजार व राज्य 30 हजार इस तरह कुल एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, चार किलोवाट व उससे ऊपर के सोलर रूफटॉप के लिए केंद्र 78 हजार और राज्य 30 हजार यानी कुल 01 लाख 08 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, इस योजना को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज और नगर निकाय को एक हजार रुपये का इंसेंटिव भी दिया जा रहा।

यूपीईआरसी ने 10 किलोवाट तक सोलर रूप टॉप स्थापना के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की छूट का आदेश जारी किया है। सोलर रूफटॉप सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए 1,079 वेंडर्स को एम्पेनल्ड किया गया है।

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ल ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 005 शुरू की गई है। वहीं, एक वाररूम भी बनाया गया है। इसमें यूपीनेडा, आरईसी व टाटा कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में सोलर समाधान पोर्टल और वेंडर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त उपभोक्ता व वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

यूपीनेडा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियां कर रहीं कार्य

हर डिस्कॉम को दिया गया लक्ष्य

ऊर्जा विभाग में डिस्कॉमवार भी पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पश्चिमांचल ने 7,25,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 3,36,863 रजिस्ट्रेशन किए और 2,77,12 आवेदन जमा किए। दक्षिणांचल ने 4,50,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 3,42,616 रजिस्ट्रेशन कर 25,768 आवेदन जमा किए। मध्यांचल ने 5,50,000 के टारगेट के सापेक्ष 4,07,625 रजिस्ट्रेशन किए और 54,074 आवेदन जमा किए हैं। वहीं, पूर्वांचल ने 5,00000 के लक्ष्य के सापेक्ष 6,78,692 रजिस्ट्रेशन किए। 59,199 आवेदन जमा किए गए हैं। केस्को ने 1,50,000 के टारगेट के सापेक्ष 19,790 रजिस्ट्रेशन किए व 5,308 आवेदन जमा किए। टोरेंट पावर ने 1,00000 टारगेट के सापेक्ष 13,089 रजिस्ट्रेशन किए और 4,123 आवेदन जमा किए। एनपीसीएल ने 25,000 के टारगेट के सापेक्ष 19,615 रजिस्ट्रेशन कर 2025 आवेदन जमा किए। वहीं, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 8,033 लोगों को 24.07 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जा चुकी है। इससे 33.2 मेगावाट की क्षमता भी स्थापित हो चुकी है। केंद्र द्वारा अभी 18,963 लोगों को सब्सिडी दी जानी है।